VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2368)

Name of Candidate	S.K. Meena		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	79007
Center	MN	Date	12/09/24

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **HINDI & ENGLISH.**
   इसमें बीस प्रश्न हैं **हिन्दी और अंग्रेजी** में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

Is student recommended for One-to-One mentoring?

Recommended	Strongly Recommended

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp. Punjab & Sind Bank), Dr. Mukherjee Nagar, Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

For one-to-one mentoring session on this copy, call us at 7042691891 or send an email to appointment@visionias.in

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q1. न्यायालयों द्वारा की जा रही व्याख्या के कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे का विस्तार हुआ है। न्यायालय के प्रासंगिक पूर्ववर्ती निर्णयों की सहायता से चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The evolving interpretation by the courts have led to the expansion of the scope of the Right to Life and Personal Liberty under Article 21 of the Indian Constitution. Discuss with the help of relevant case laws. (Answer in 150 words) 10

अनुच्छेद 21 के अनुसार 'विधि की स्थापित' प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को उसकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से प्रतिबंधित नहीं किया जायेगा।

जीवन के अधिकार के रूप में न्यायालयों द्वारा इसकी PIL व न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उदारवादी व्याख्या कर विस्तार किया है।

① हाल ही में जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार।

② मेनका गांधी वाद 1978 में विधि की प्रक्रिया को 'विधि की उचित प्रक्रिया' बताकर विधायिका पर भी प्रतिबंध

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) अरुणा शानबाग केस मे Art 21 के सम्मानपूर्वक मौत का अधिकार।

(4) पुट्टुस्वामी वाद 2017 मे निजता का अधिकार के रूप मे विस्तार

(5) सूचना का अधिकार Art 19 व Art 21 दोनों मे।

(6) देश के अंदर भ्रमण व देश के बाहर जाना का अधिकार।

(7) समलैंगिक पहचान (नालसा केस) का अधिकार।

(8) स्वच्छ पर्यावरण, जेल मे उचित दशाओं, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य का अधिकार

(9) शिक्षा का अधिकार Art 21 के अंदर। (10) निजता का अधिकार

फलतः यद्यपि उदार व्याख्या मानवाधिकारों को बढाती है किर न्यायिक संयम जरूरी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8A भारत में चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को किस प्रकार सुरक्षित रखती है। विश्लेषण कीजिए (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Analyse how Section 8A of the Representation of the People Act, 1951 preserves the integrity of the electoral process in India. (Answer in 150 words) 10

RPA 1951 के माध्यम से निर्वाचन आयोग निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव के अनुच्छेद (Art 324) को सफल बनाती है।

8A धारा कुछ मामलो मे दोषी प्राप्त व्यक्तियों को संसद या विधानसभा सदस्य के रूप मे निर्वाचन के लिए अयोग्य ठहराती है।

धारा 8A के तहत :—

(i) UAPA 1967 के तहत अपराध
(ii) देश की एकता, अखण्डता के विरुद्ध गतिविधि
(iii) सार्वजनिक सेवा से अवैध / भ्रष्टाचार के लिए बर्खास्त व्यक्ति

(iv) धार्मिक वैमनस्य, सती प्रथा, दहेज प्रथा को बढ़ावा देने वालों

- चुनावों में भाग लेने के लिए अयोग्य
- 6 साल तक जेल व अवैधता/निर्योग्यता निर्धारण
- 8(1) का धारा 125
- etc

इसके द्वारा भी 8(1), 8(2), 8(3), आदि द्वारा भी विभिन्न अपराधों के लिए प्रावधान है

जिससे

- राजनीति का अपराधीकरण से सुरक्षा
- जनता के जानने के अधिकार को सशक्त
- बाहुबल प्रभाव की दक्षता
- निष्पक्षता पारदर्शिता

फलतः चुनावों को सही मायनों में लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास करता है

Q3. भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची को प्रारंभ में किन उद्देश्यों के साथ प्रस्तुत किया गया था? क्या उच्चतम न्यायालय नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी कानून की समीक्षा कर सकता है? न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों की सहायता से चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

With what objectives was the Ninth Schedule of the Indian Constitution initially introduced? Can the Supreme Court review a legislation that has been placed in the Ninth Schedule? Discuss with the help of case laws. (Answer in 150 words) 10

(1951) प्रथम संविधान संशोधित द्वारा शामिल संविधान की 9वीं अनुसूची न्यायिक हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करती है।

प्रारंभ में उद्देश्य :

① भूमि सुधार को सफल बनाना

② भूमि पुन: वितरण के कानूनों को मूल अधिकार (तत्कालीन संपत्ति का अधिकार) से बचाना।)

③ न्यायिक हस्तक्षेप रोकना ⇒ अविलंब कार्य

SC द्वारा ~~समीक्षा~~ की संभावना : —

* केशवानंद भारती वाद 1973 के बाद इसमे शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

* न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल संरचना का भाग है।
* आई. आर. कोहिलो वाद 2007 के की केशवानंद वाद 1973 की पुष्टि की गई व SC द्वारा मूल अधिकार मूल संरचना के आधार पर 9वीं अनुसूची की 1973 के बाद के विषयों की जाँच की जा सकती है।

वर्तमान में 9वीं अनुसूची महत्व नहीं रखता है इसमे शामिल विषय भी मूल उद्देश्य से भिन्न है।

Ex - तमिलनाडु 69%. आरक्षण

फलत: विधि आयोग के व पुंछी आयोग के इस अनुसूची व इसमे शामिल विषयों की जाँच व तार्किकीकरण को बल दिया है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q4. ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) द्वारा प्रदान की जाने वाली विवादों के उचित, त्वरित और प्रभावी समाधान तक पहुंच कई चुनौतियों से घिरी हुई है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Online Dispute Resolution's (ODR) promise of access to just, speedy and effective resolution of disputes is beset with several challenges. Discuss. (Answer in 150 words) 10

ऑनलाइन विवाद समाधान से तात्पर्य इंटरनेट के प्रयोग द्वारा विवादों का ADR की प्रक्रिया या कानूनी प्रक्रिया से समाधान करना है।

चुनौतियाँ : →

1) पहुँच :→ अजागरूकता
- 74% शिक्षा दर
- 24% डिजिटल शिक्षा
- बिजली 24×7 नहीं
- ग्रामीण भारत

2) इंफ्रा अभाव → बाधा आना

3) अविश्वसनीयता

4) अपील फिर की करना

(3) सकारात्मक रवैया अभाव

(4) व्यापक खर्च बढ़ना

(5) निजता का उल्लंघन का संकट |

(6) डाटा संरक्षण नियमन

(7) मूल अपराधी मंत्रालय को न पकड़ पाना |

Ex – 10% से कम केस

फलत: इसमें सुधार के लिए प्रयास हो — डिजिटल इंडिया
— ब्रॉडबैंड भारत
— भारत नेट
— 24×7 बिजली

जैसे

Q5. केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यालय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के कारण सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम निरर्थक हो गया है। विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The Right to Information (RTI) Act has fallen into redundancy owing to the issues faced by the Office of the Central Information Commission. Analyse. (Answer in 150 words) 10

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)

सूचना के अधिकार के अधिकार का शीर्ष समन्वयन करने वाली संस्था है।

★ CIC व्यवस्था

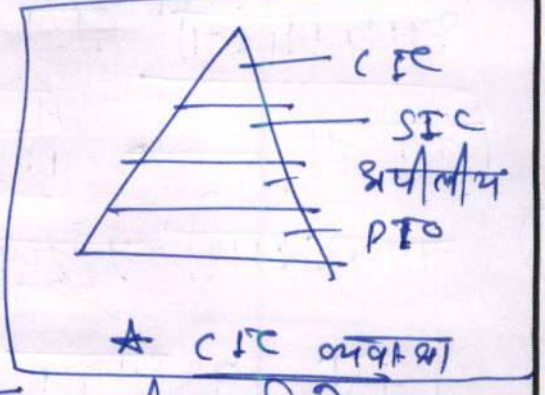

लेकिन वर्तमान मे SIC के पास 4 लाख केस लंबित है व सरकारी अधिकारियों पर दण्डता की दर मात्र 2-3 % होना इस तंत्र की विफलता दिखाता है।

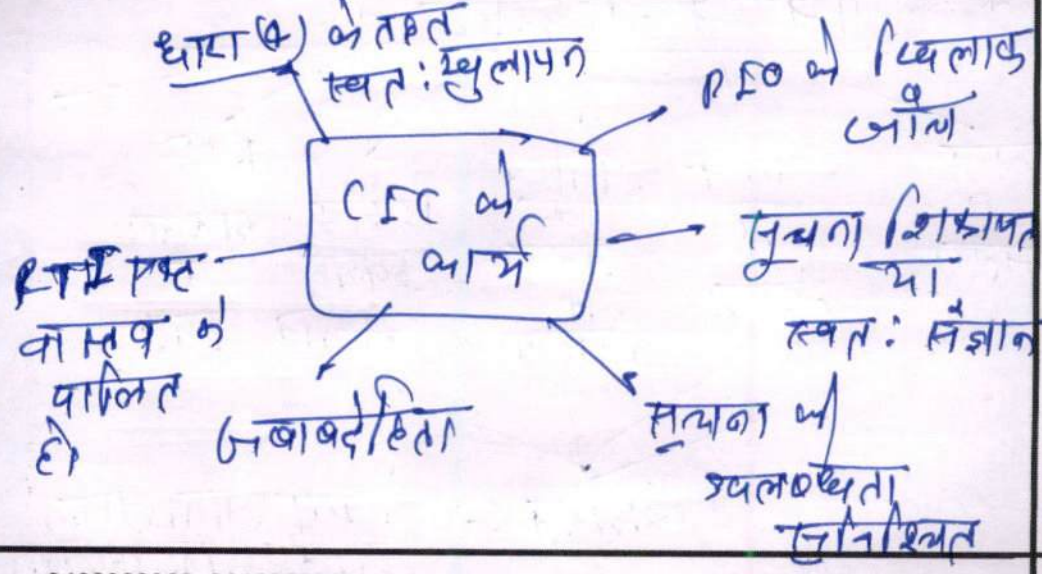

2368
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

CIC के सामने समस्याएँ :-

① नियुक्ति में कार्यपालिका हस्तक्षेप

② नियुक्ति विलंबता व राजनीतिकरण

③ CIC 'दंत विहीन बाघ' की तरह जिसको वास्तविक शक्ति नहीं।

④ अधिकारियों द्वारा प्रदत्त सूचना पर निर्भरता → हितों का संघर्ष

⑤ नौकरशाही प्रभुत्व → रूढ़ मानसिकता

⑥ वित्त व मानव संसाधन क्षमता अभाव ⑦ अत्यधिक लंबित मामले

⑧ फलत: RTI एक्ट के तहत लगाये गये आवेदन पर

- सूचना न मिलना
- समय पर न मिलना
- पर्याप्त व सटीक न मिलना
- रिकॉर्ड प्रबंधन अभाव
- RTI कार्यकर्ता पर हमले

→ शिकायत CIC के पास जाना लेकिन उसकी [illegible]

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q6. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) ने भारत में जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस प्रकार परिवर्तित कर दिया है? इसकी पूर्ण क्षमता का लाभ उठाने में आने वाली प्रमुख बाधाएं क्या हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

How has Information and Communication Technology (ICT) transformed the governance landscape at the grassroots level in India? What are the key obstacles in leveraging its full potential? (Answer in 150 words) 10

शासन मे सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग को सुशासन बनाने की क्षमता रखता है।

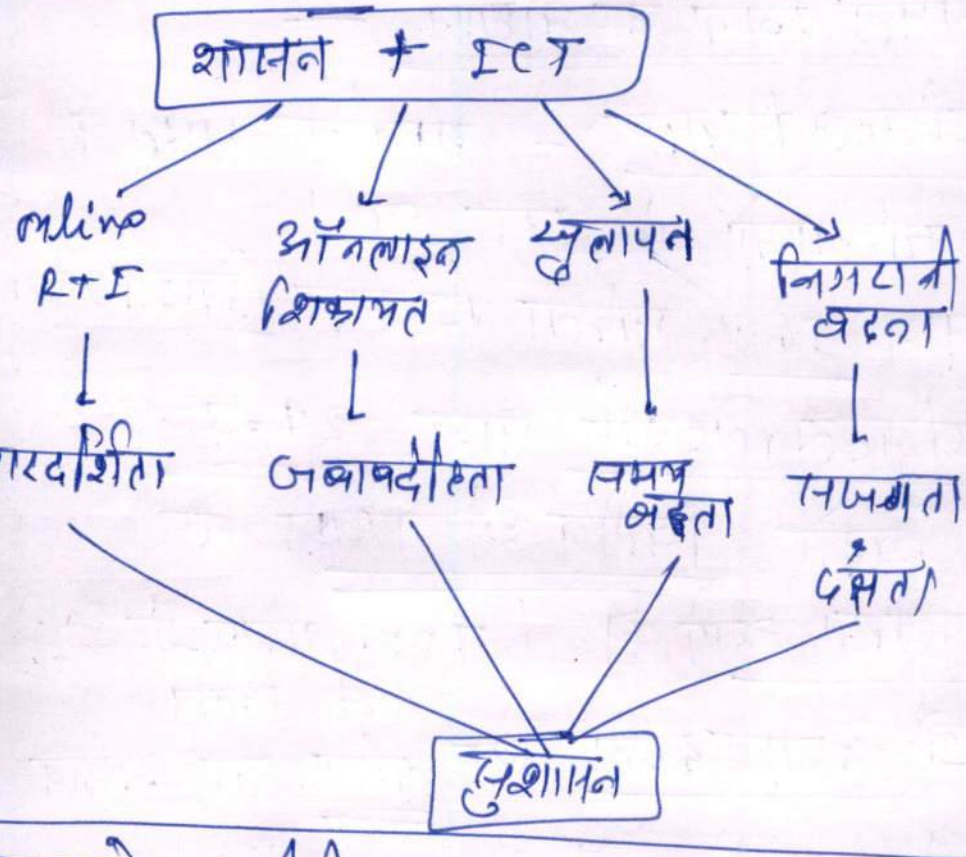

भारत मे जमीनी स्तर पर उदाहरण! —

① मेघालय के सोशल ऑडिट

② विजयवाड़ा पंचायत मे अनियमितता खुलासा

③ e-NAM द्वारा कृषक सशक्त

(4) सेवा प्रदाय गुणवत्ता बढ़ना

(5) 300 से ज्यादा योजनाओं में DBT का प्रयोग → लक्षित प्रयोग → PM उज्ज्वला, NFSA, मनरेगा।

(6) लाभार्थी सटीक पहचान
↳ लीकेज का समाधान

पूर्ण समता उठाने के बाधाएं :—

(1) डिजिटल डिवाइड — ग्रामीण भारत व महिलाओं के साथ यह। मात्र 36% महिला डिजिटल डिवाइस प्रयोग

(2) डिजिटल लिटरेसी मात्र 24.7% है जो बढ़ते वित्तीय धोखाधड़ी को परिलक्षित करती है (75% साइबर फ्रॉड 2022-23 में वित्तीय)

(3) जागरूकता व कौशल का अभाव

(4) नौकरशाही लचीला व प्रतिक्रियाशील न बनना।

(6) संघीय आपत्तियाँ

(5) नियमित निगरानी अभाव

समावेशता, ग्रामीण — (प्रभाव) → डिजिटल इंडिया को सफल, आर्थिक रूप, भागीदारी

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q7. सिविल सेवाओं का राजनीतिकरण भारत में शासन के 'स्टील फ्रेम' को किस प्रकार नष्ट कर देता है? इस प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए कौन-से उपाय अपनाए जा सकते हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

How does the politicization of the civil services corrode the 'steel frame' of governance in India? What measures can be implemented to counteract this effect? (Answer in 150 words) 10

सिविल सेवाओं का राजनीतिकरण से तात्पर्य सिविल सेवक भर्ती, नियुक्ति, स्थानांतरण, प्रोमोशन राजनीति के लक्ष्यों प्रेरित होकर करना।

स्टील फ्रेम
- स्थायी
- सदैव निष्पक्ष
- तटस्थ
- मजबूत
- दृढ़ता
- भरोसेमंदता

राजनीतिकरण से प्रभाव
- मूल्यों का पतन
- निष्पक्षता बाधित
- नौकरशाही (गठजोड़) नेता /अपराधी
- भ्रष्टाचार → भारत की रैंक 93rd (2024) भ्रष्टाचार सूचकांक
- सेवा प्रदान गुणवत्ता पतन
- जनकल्याण की उपेक्षा

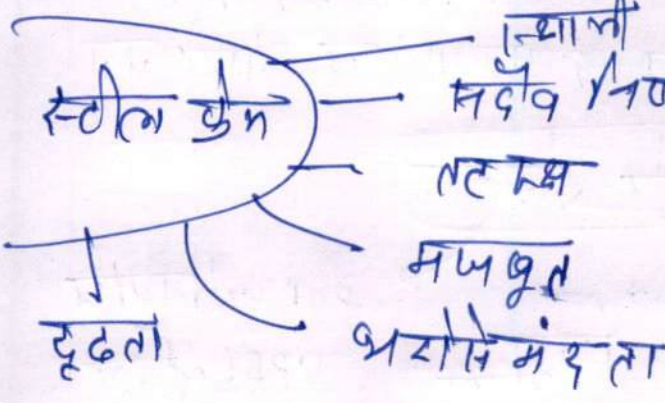

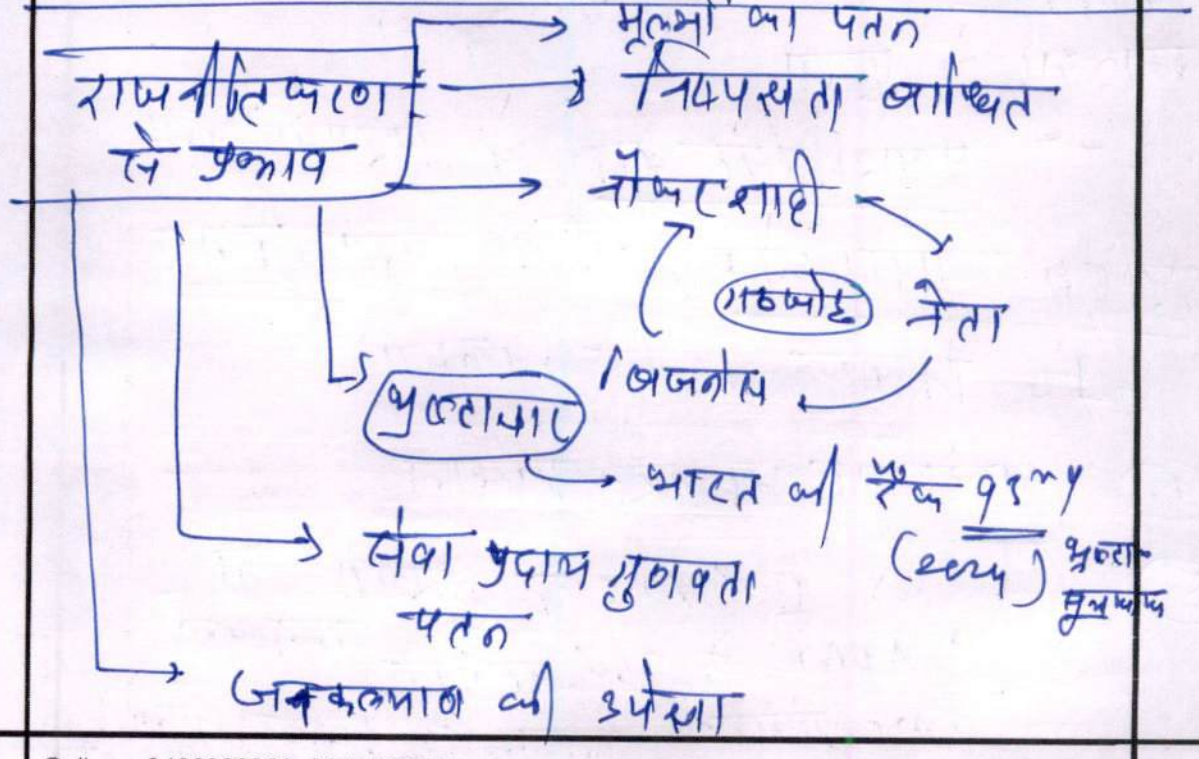

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रतिवाद के उपाय! —

① भर्ती के स्तर पर UPSC की तरह सशक्त निकायों द्वारा स्वच्छ भर्ती हो।

② प्रशिक्षण के समय → गैर-राजनीतिक दृढ़ता मूल्य
→ लोक सेवा मूल्य
→ मिशन कर्मयोगी
→ Ethics field visit परीक्षण
→ चौलक जमिति के मूल्यों का आंतरीकरण

③ राजनीतिक हस्तक्षेप रोकना
→ Art 311 के तहत ईमानदार को सुरक्षा
→ कार्यकाल में स्थायित्व
→ बिना कारण स्थानांतरण न हो
→ DoP की नियुक्ति UPSC पैनल से हो
↳ प्रकाश सिंह वाद के सुझावों यथा पुलिस स्थापना बोर्ड, पुलिस सुरक्षा निकाय जैसे निकाय सभी विभागों।

④ भ्रष्टाचार पर त्वरित प्रशासन

⑤ ↳ 2nd ARC के सुझावों का कार्यान्वयन
↳ APAR के 360° मूल्यांकन
↳ inter प्रशिक्षण मत: बहुविभागीय कार्यक्रम हों।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q8. लैंगिकता वृद्धावस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। भारत में सामाजिक अलगाव और वंचना का सामना करने वाली बुजुर्ग महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Gender is an important dimension of ageing. What measures can be taken to solve the problems of elderly women facing social alienation and deprivation in India? (Answer in 150 words) 10

भारत की 10.1% आबादी वृद्ध है। (2011 जनगणना) इसका लैंगिक प्रतिरूप देखा जाये तो भारत मे महिला जीवन प्रत्याशा पुरुषों से अधिक है।

फलत: भारत मे वृद्ध महिलायें ज्यादा है (लगभग 65%) जिन पर जनसंख्या नीति 2000 सहित सभी ध्यान नहीं दिया गया।

वृद्ध महिलाओं की समस्या:

- पीढ़िगत तनाव
- स्वास्थ्य संबंधी परेशानी
- एकल जीवन
- आर्थिक असहाय — 78% बुजुर्ग बिना स्वास्थ्य बीमा
- अकेलापन — लगभग 90% महिला बुजुर्ग डिजिटल अज्ञान
- 80% बुजुर्ग भरण पोषण के लिए परिवार निर्भर

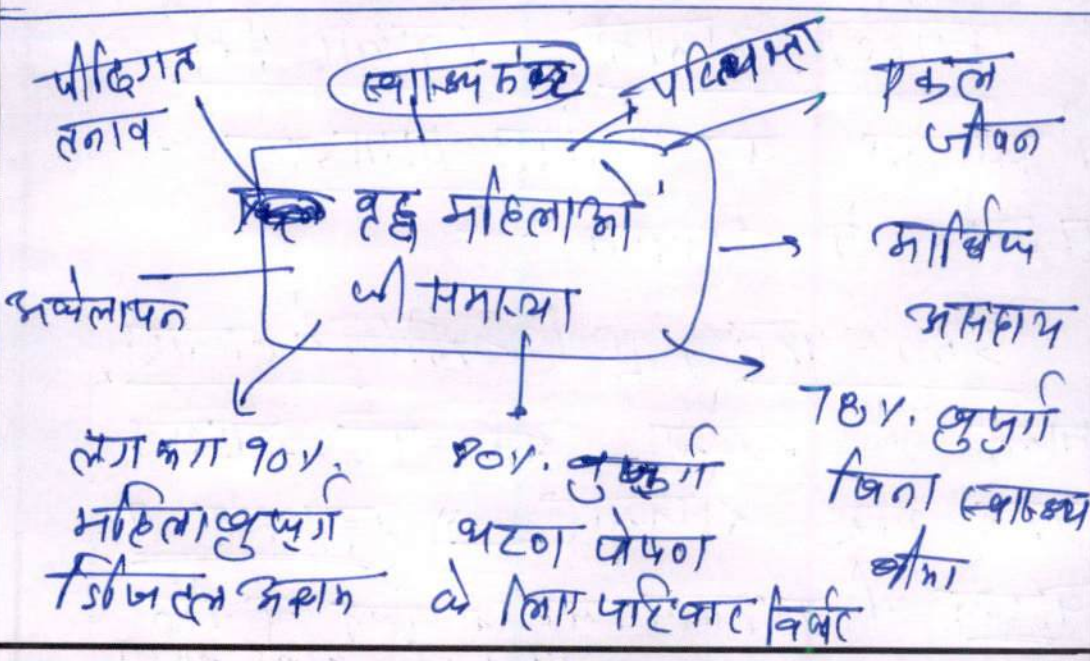

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

समाधान के उपाय : —

① नई जनसंख्या नीति की आवश्यकता जो Ageing की समस्या को ध्यान रखे

② महिला अनुकूल नीति बनाना
उदा० => माता-पिता भरण पोषण एक्ट 2007 को अधिक महिला संबंधी बनाना।

③ बीमा व पेंशन कवर का विस्तार 100% हो।

④ मूल्य आधारित शिक्षा व सामाजिक मूल्यों का निर्माण हो।

⑤ महिला आश्रमों, स्वाधार गृहों की स्थापना व सिविल सोसाइटी के सहयोग से प्रबंधन।

⑥ SAGE पहल, IInd जनांकिकी लाभांश मानने की प्रवृत्ति, पुन: कौशल प्रदान कर रोजगार => वृद्धावस्था व बीमारी की गहनता का आंकलन कर नीति निर्धारण करना चाहिए

Q9. भारत और अफ्रीकी देशों के बीच राजनीतिक एवं आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देने में भारतीय प्रवासी क्या भूमिका निभा सकते हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

What role can the Indian diaspora play in fostering political and economic engagement between India and African countries? (Answer in 150 words) 10

अफ्रीका भारत के लिए संसाधन सहित रणनीतिक महत्व (UNSC) का माध्यम है तो अफ्रीका के लिए भारत विकास, प्रशिक्षण, कौशल का भरोसेमंद स्रोत है।

अफ्रीका के प्रवासी भारतीय प्राचीन गिरमिटिया से लेकर वर्तमान मजदूर व मारवाड़ी व्यापारी के रूप मे मौजूद है। Ex केन्या, तंजानिया, द्वीपीय देश इत्यादि

राजनीतिक व आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने मे महत्व। — (प्रवासी महत्व)

① नजदीकियाँ बढ़ाना

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) पश्चिमी हिंद महासागर में भारत की शीर्ष पद बढ़त में

(3) सांस्कृतिक जुड़ाव (9) छोटा भाई
└ व्यापार कैपम पंजीकार में
└ फिल्म उद्योग विस्तार

(4) पोर्ट ब्रांच के रूप में

(5) भारत की छवि बेहतर व Net Security provider के रूप में

6)

(1) IORA, EPOI, IONS, EFC-DOR आदि की निकलता

(7) UNSC में भारत की सीट

(8) यूरोपियन यूनियन का G-20 में भारत द्वारा समर्थन कतर द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा किया जाना चाहिए। (जैसे AAGC में तीव्रता व सागर जैसी पहलों व GTLC, HADR द्वारा बढ़ाया जा सकता है)

Q10. अपने प्रारंभ के एक दशक से भी अधिक समय बाद, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लाभ, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए, भ्रामक साबित हुए हैं। टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

More than a decade after its inception, the benefits of the Belt and Road Initiative have proven to be illusory, especially for developing countries. Comment. (Answer in 150 words) 10

बेल्ट व रोड प्रोग्राम वस्तुतः आर्थिक विकास की आड़ में चीन की विस्तारवादी नीति का ही आयाम साबित हुआ है।

लाभों की भ्रामकता :

① चीन की ऋण जाल की नीति का शिकार — जिबूती, इटली, श्रीलंका

② देशों की संप्रभुता से समझौता

③ CPEC का बाधित होना

④ स्थानीय रोजगार की जगह मात्र चीनी बाहरी लोगों को रोजगार

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(5) ऋण पुनर्गठन के अभाव में आर्थिक अस्थिरता व अशांति
यथा :- श्रीलंका 2022

(6) CPEC में शामिल देशों में विकास का अभाव
- लोगों के विरोध
- बंद करने की मांग
- Go Back China के नारे

फलतः भारत व विश्व की शक्तियों को चाहिए कि वे Build Back Better, PGII, IMEC कॉरिडोर, ऋण विकल्प, व देशों को सहायता देने का QUAD, AUKUS, SQUAD द्वारा चीन को संतुलित करे

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q11. भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के समक्ष आने वाली वित्तीय बाधाओं पर चर्चा कीजिए। उनके राजस्व संसाधनों में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss the financial constraints faced by the Panchayati Raj Institutions (PRIs) in India. What measures can be taken to augment their revenue resources? (Answer in 250 words) 15

73 वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की Art-40 को साकार करने वाली संस्थाएँ 3-F के संकट ग्रस्त है (फंड, फंक्शनरीज, फंक्शन) विभागीय PRI पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार वे वित्त के लिए 95% अनुदान पर निर्भर है।

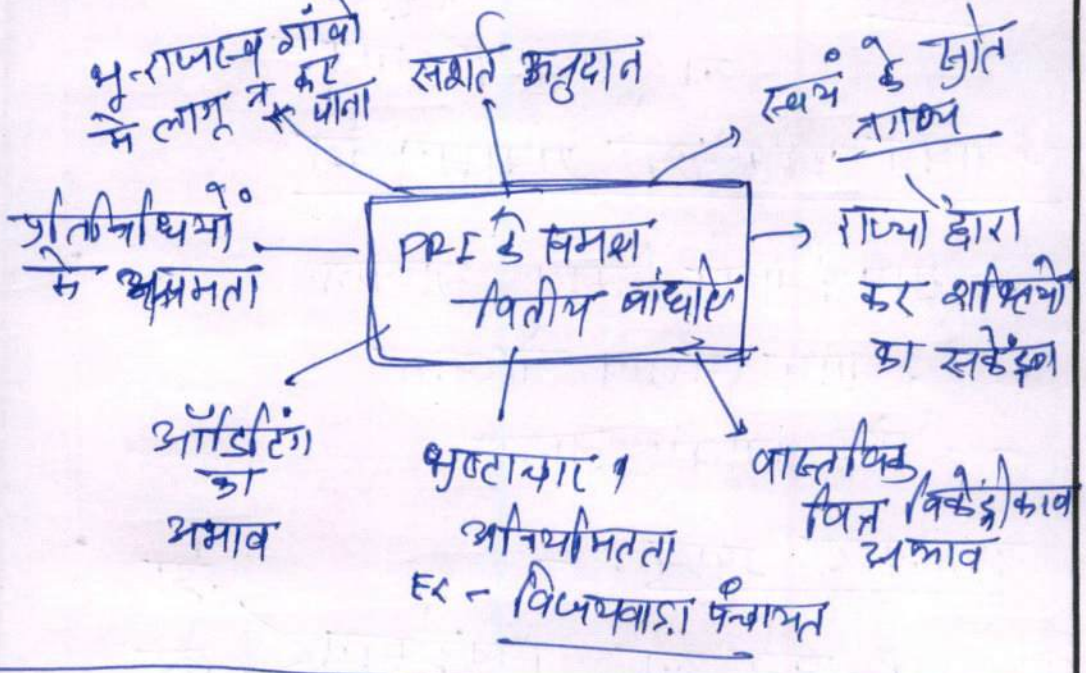

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

फलतः मूल बाधाएँ राज्यों की इच्छाशक्ति का अभाव व पंचायतों के पास सीमित राजस्व क्षमता होना है।

जैसे - किसानो पर कर न लगाना
- गांवो का सामंजस्यपूर्ण माहौल
- महिला सरपंचपति कल्चर

राजस्व संसाधन वृद्धि के उपाय

① वित्त का वास्तविक विकेंद्रीकरण :- अनुसूची 11 के 29 विषय देना।
उदा० - गोवा की कलंगुट पंचायत का राजस्व मॉडल

② पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षण तंत्र
- ग्राम पंचायत विकास योजना
- ई-ग्राम स्वराज योजना
- नैय नवाचार लाना

③ नवाचारी उपाय :-
(i) CSR खर्च का विकेंद्रीकरण < इंफ्रा / रोड
(ii) पार्किंग की, 'उपयोगकर्ता शुल्क' पार्किंग

(iii) पंचायतों का स्थानीयता अनुरूप सेवा / व्यापार / बाजार / पर्यटन हब बनाना

उदा० - ग्रामीण पर्यटन > शुल्क लगाना
- कृषि अध्ययन यात्रा

(4) म्युनिसिपल बांड की तरह PRI के मॉडल पर पंचायतों के लिए बांड लाना

Ex - PUNE नगरपालिका बांड

(5) 3-F विकेंद्रीकरण <
- पृथक प्रशासनिक काडर
- वित्त के विषय
- वित्त की शक्ति

जिससे आगे भी

सुझाव:
- AE, GES प्रयोग
- मनरेगा से जोड़कर
- RTI
- जवाबदेहिता
- राष्ट्रीय PRI डैश बोर्ड
- CAG द्वारा Audit
- प्रशिक्षण

आदि द्वारा न केवल वित्तीय बल्कि सर्वांगीण सशक्त पंचायत बना सकते हैं।

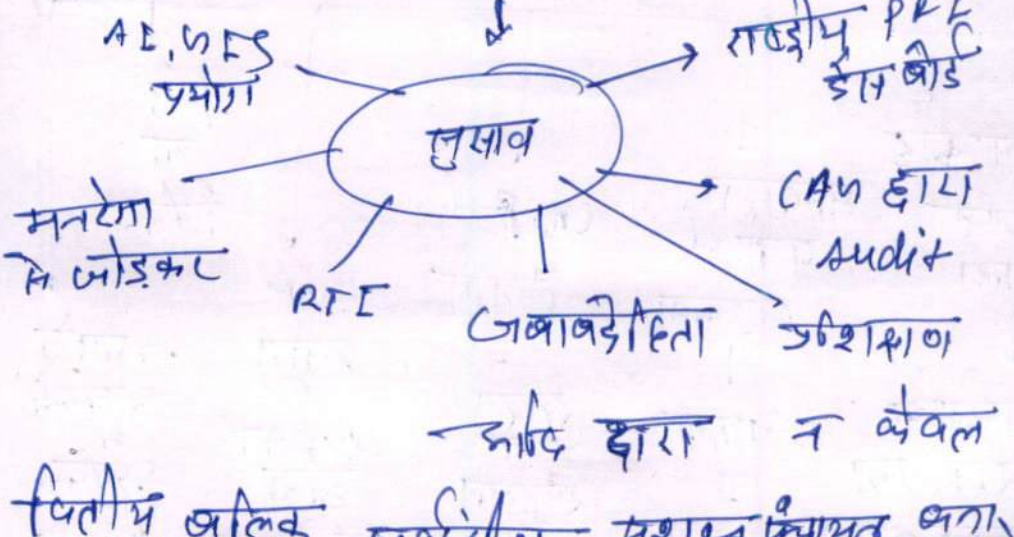

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q12. भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 ECI की स्वतंत्रता को किस प्रकार प्रभावित करेगा? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss the role of the Election Commission of India (ECI) in ensuring free and fair elections in India. How will the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 impact the independence of the ECI? (Answer in 250 words) 15

Art 324 के माध्यम से चुनाव आयोग देश मे निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव के अधिरोप की भूमिका निभाता है।

निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव सशक्त लोकतंत्र का आधार होता है।

ECI की भूमिका – ECI जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1950 व जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के माध्यम से।

- मॉडल कोड कंडक्ट लागू → दुष्प्रचारों पर एक्शन लेना → संतुलन बनाना
- मतदाता सूची की सटीकता → अद्यतन मतगणना
- CAPF की तैनाती → सुरक्षा व संतुलन
- EVM प्रयोग VVPAT द्वारा परीक्षण
- दलों का पंजीकरण
- जनता के अधिकारों के अनुरूप

अतः ECI भारत के संविधान, संसद के एक्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप निष्पक्ष तंत्र की स्थापना करता है।

हाल ही में अनूप बर्णवाल केस फैसले को उलटते हुये पारित मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त एक्ट 2023 ECI के स्वतंत्रता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।

CEC व EC एक्ट 2023 प्रावधान

- पुनः नियुक्ति नहीं
- EC को हटाना आसान — CEC के समान सुरक्षा नहीं
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति — समिति जो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री व नेता विपक्ष से बनी होगी के आधार पर
- खोज समिति में कैबिनेट सचिव
- कार्यकाल — केंद्र सरकार कहे तब तक या 65 y. तक
- योग्यता
  - चुनाव प्रबंधन अनुभव
  - केंद्र में सचिव रैंक (न्यूनतम)

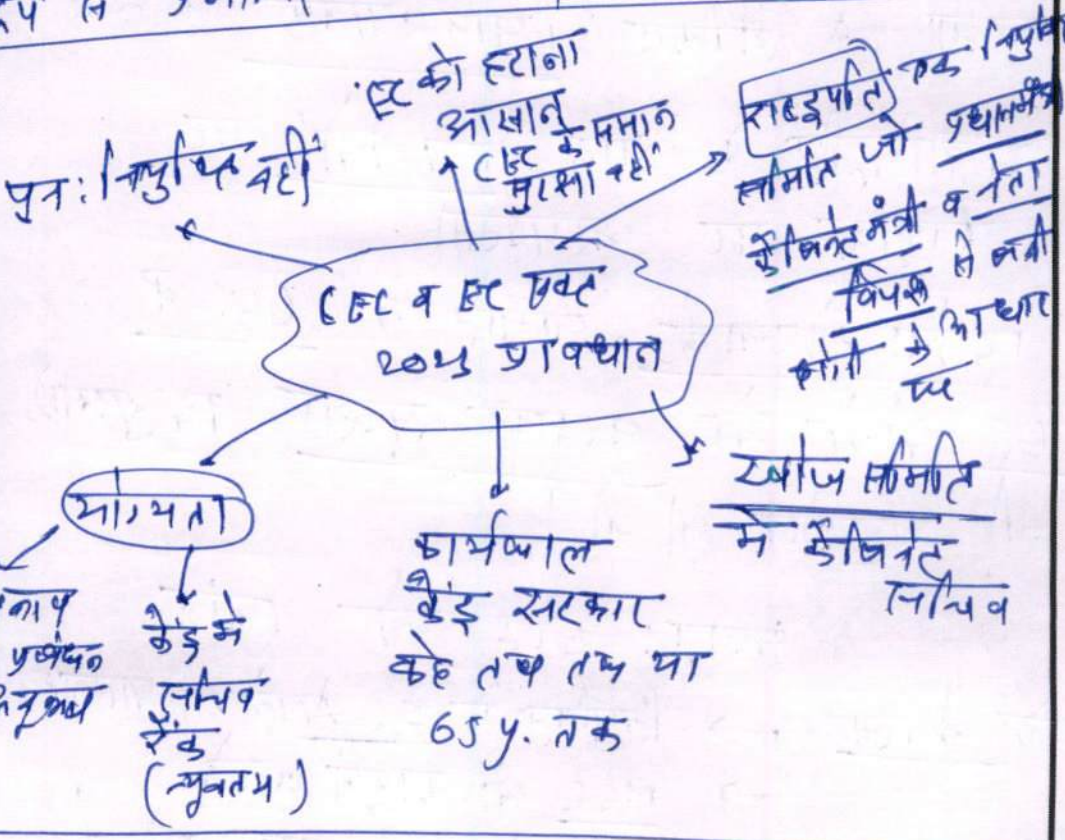

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

नकारात्मक प्रभाव

① नियुक्ति समिति में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ सकता

② सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति समिति में C.J.I को शामिल किया, इसके विरुद्ध

③ ECI अर्द्ध न्यायिक कार्य को करता है लेकिन सिविल सेवक की शर्तें

④ सेवानिवृत्ति के बाद अन्य पदों पर नियुक्ति पर अस्पष्टता

⑤ दिनेश गोस्वामी समिति ने CEC व EC दोनों को बराबर सुरक्षा (पद सुरक्षा) की अनुशंसा की थी।

स्वतंत्रता पर सकारात्मक प्रभाव

- पुनः नियुक्ति नहीं
- CEC के पद की सुरक्षा
- वेतन व भत्ते में अपरिवर्तन

फलतः ECI को स्वतंत्र बनाने के लिए

- → नियुक्ति में SC फैसले की पालना
- → MCC को कानूनी बनाने
- → दलों के पंजीकरणरद्द करने की शक्ति
- ECI को वित, मानव संसाधन स्वायत्तता

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q13. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 ने भारत में वंचित समुदायों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने और उन्हें भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 has played a significant role in preventing atrocities and providing protection against discrimination of marginalized communities in India. Analyse. (Answer in 250 words) 15

SC-ST एक्ट 1989 मुख्यत।

अनुच्छेद 17 की भावना सहित समानता के मूल्य की स्थापना व सदियों से शोषित रहे समाज की चेतना को तोड़ने का कानूनी हथियार है।

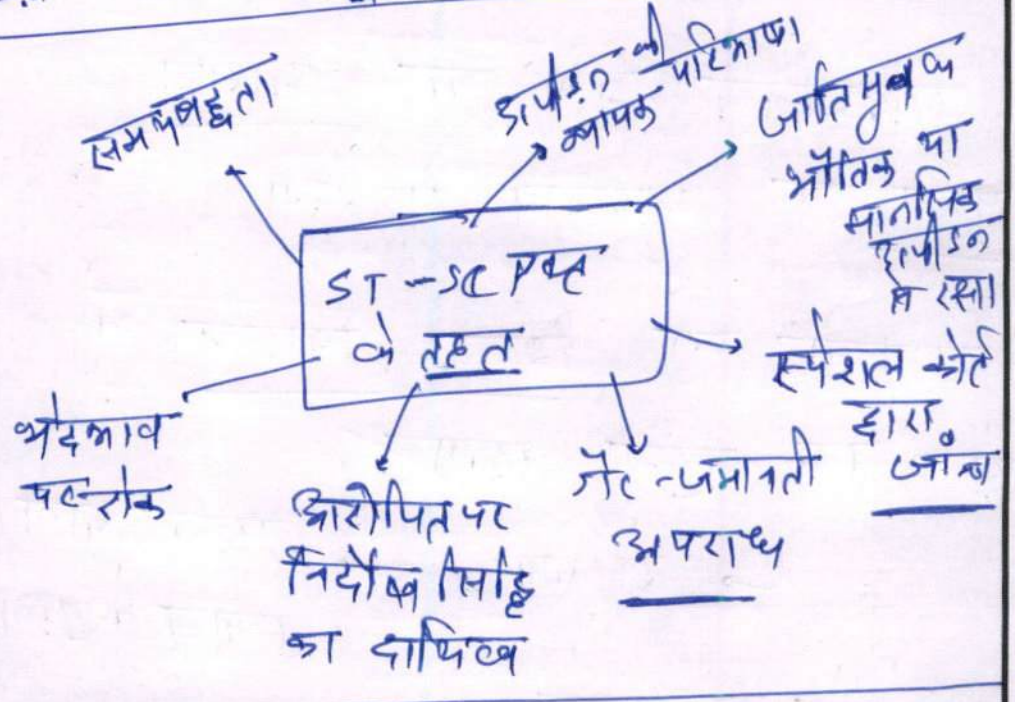

ST-SC के विरुद्ध अपराधों व चेतना को रोकने में महत्वपूर्ण रोल! →

① शोषित वर्ग को सशक्त बनाकर कि

यह दुष्चक्र समाप्त हो सकता है।

(सजा) शोषण] शिकायत जाँच

② शोषित शोषक वर्ग का अपराधियों पर निरुत्साह व निवारक प्रभाव

③ कार्यस्थल पर समावेशी माहौल

④ सार्वजनिक स्थलों पर आसान पहुँच व भेदभाव से रक्षा।

⑤ समाजों का शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवा तक पहुँच बढ़ना

↳ रोजगार → मुख्य धारा समाज में जुड़ना

⑥ मनोवृत्ति बदलाव —

यद्यपि इस एक्ट के कारण परोक्ष रूप से कुछ <u>समस्याएँ बनी</u> है:

- सामाजिक भेदभाव की जड़ता को वैधता मिलना
- कानून का दुरुपयोग
  - निर्दोषों को सजा
- दोषसिद्धि की न्यून दर
- वास्तविक न्याय न मिल पाना
  - ↳ पुलिस द्वारा समझौता
- घृणा बढ़ना समाज में

फलतः आज भी या तो कटवाना <u>ऊना जैसी दलित हिंसा</u>, <u>दलित बारात को घोड़ी</u> पर न जाने देना जैसे मामले है तो <u>कानून के माध्यम</u> से निर्दोष को सजा के मामले है। जरूरत है एक्ट की पुन: जांच की जिससे <u>परिभाषा व दायरों में स्पष्टता आये</u> व <u>वास्तविक दोषियों</u> पर एक्शन हो व <u>दुरुपयोग</u> को <u>शून्य</u> किया जाये। (विधि आयोग सिफारिश)

2368
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q14. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के कार्यों पर चर्चा कीजिए। महिलाओं की समस्याओं से निपटने में सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होने से आयोग को क्या लाभ होता है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss the functions of the National Commission for Women (NCW). How does the Commission benefit from having the powers of a civil court in dealing with women's issues? (Answer in 250 words) 15

राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट 1992 द्वारा स्थापित यह सांविधिक आयोग देश मे आधी आबादी की सुभेद्यता व सुरक्षा को प्रतिबिंबित करती है।

NCW के कार्य :-

1. महिला शोषण शिकायतों की जाँच करना। Ex— कोलकाता रेप केस
2. महिला अत्याचारों पर स्वत: संज्ञान लेना।
3. महिला सुरक्षा उपायों (संवैधानिक, वैधानिक, नीतिगत) के कार्यान्वयन का आंकलन, सरकार को सुझाव व विश्लेषण करना।
4. वृद्ध महिला, पॉक्सो पीड़ित बालिका, परित्यक्त महिलाओं के पुनर्वास

(5) महिला संबंधी नीतियों का प्रचार - प्रसार
Ex - स्वाधार गृह, अंतर्राष्ट्रीय मंचों यथा बीजिंग योजना पर से जुड़ना।

सिविल न्यायालय की शक्ति से लैस :—

(1) किसी को मामले पर समन जारी कर सकना
(2) रिकॉर्ड प्राप्त कर सकना
(3) जाँच की शक्ति
(4) प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का प्रयोग करना।
(5) सजा या कार्यवाही की सख्त अनुशंसा कर सकना।

यद्यपि इसके बाद भी NCRB का डेटा कहता है 2022-23 के मध्य महिला अपराधों में 4%

की वृद्धि हो गई है क्योंकि

NCW ⇒
- केवल सलाहकारी
- दण्ड देने की शक्ति नहीं
- मामलों का राजनीतिकरण
- स्वायत्तता का अभाव आदि

केवल शब्दों तक प्रभावी जैसी समस्याओं से ग्रसित है व महिला समस्याएँ मात्र कानूनी नहीं वह सामाजिक, मानसिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जड़ताओं का संयुग्मन है।

सुझाव
- पिंक कॉलर जॉब से STEM को बढ़ावा
- NCW को सशक्तता → संवैधानिक दर्जा, पूर्ण स्वायत्तता
- केयर इकॉनोमी में निवेश व महिला के द्वारा 76% अवैतनिक कार्य को महत्व
- ग्लास सीलिंग रूढ़ीकरण को तोड़ना (मात्र 13.7% महिला उद्यमी)
- महिला नियोजनीयता बढ़ाना → शिक्षा, कौशल (65%), रोजगार (93% अनौपचारिक)

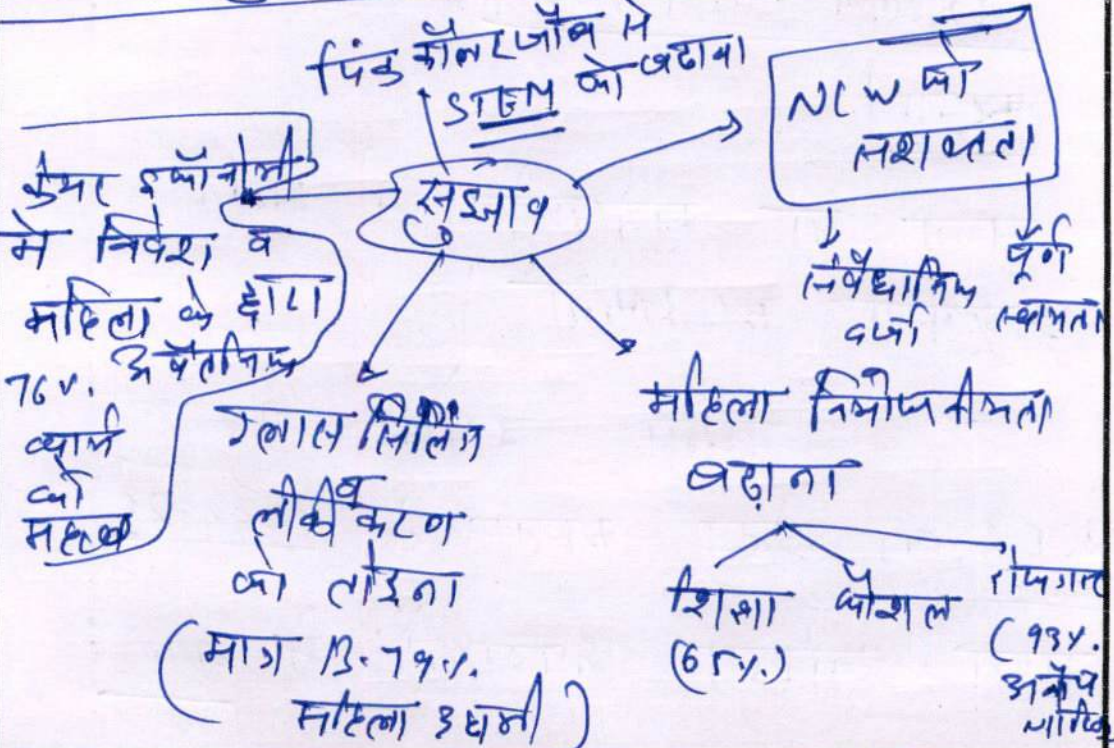

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q15. भारत में बाल यौन शोषण के मुद्दे का समाधान करने में POCSO अधिनियम, 2012 की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Critically analyse the effectiveness of the POCSO Act, 2012 in addressing the issue of child sexual abuse in India. (Answer in 250 words) 15

पोक्सो एक्ट. 2012 बच्चों के स्वास्थ्य व मानव विकास की धारणा [Art 39(च)] को सफल बनाने के लिए सशक्त कानून है।

18 y. से कम उम्र की लड़की के साथ लैंगिक शोषण इस कानून के तहत अपराध है।

प्रभावशीलता :-

1. स्पेशल पोक्सो कोर्ट के माध्यम से तुरंत व सटीक कार्यवाही।
2. यौन शोषण की जाँच में बाल-अधिकारियों के अनुरूप माहौल बनाना
3. निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी दोषी की

2368
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) लैंगिक उत्पीड़न को व्यापक परिभाषा

अश्लील साहित्य, यौन इशारे, छूना, पेनेट्रेटिव शोषण

(5) समयबद्ध एक्शन व DSP लेवल के अधिकारी द्वारा जाँच।

फलत: इससे इस अपराध को रोकने मे मदद मिली है।

अप्रभावशीलता / समस्याएं :

(1) लैंगिक तटस्थ न होना - 18 y से छोटे लड़को को संरक्षण नहीं

(2) दुरुपयोग व बदला लेने के द्वेष भाव के मामले बढ़ना।

(3) बदलता दौर व जेन Z :-
16 साल तक के बच्चे सोशल मीडिया के दौर मे यौन ~~संबंधों~~ मे खुलापन — (7) बालविवाह → संबंध

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) सहमति से यौन संबंधो पर संकट

(5) ~~दोषसिद्धि~~ की कम दर

(6) न्यायिक वाद बढ़ना

फलत: हाल ही मे बनी बाल अधिकारों संसदीय विभागीय समिति ने आयु के संदर्भ मे जाँच कि व 18 से घटाकर 16 वर्ष करने का ही सुझाव दिया।

फलत: इस एक्ट मे सुधार की आवश्यकता है:।

→ 18 से घटाकर उम्र 16 की जा सकती है

→ कम उम्र के मामलो मे न्यायालय रियायत बरत सकता है यदि सहमति के बाद यौन संबंध हो

— एक जाँच आयोग जो मामले की व एक्ट की उपयुक्तता की जांच करे का गठन हो

"चाहे 100 अपराधी छूट जाये लेकिन निरपराध को सजा न मिले"

Q16. भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Critically evaluate the implementation of the Smart Cities Mission in India. (Answer in 250 words) 15

स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में प्रत्येक 100 शहरों को नवाचारी समाधानों के माध्यम से स्मार्ट बनाने का मिशन है।

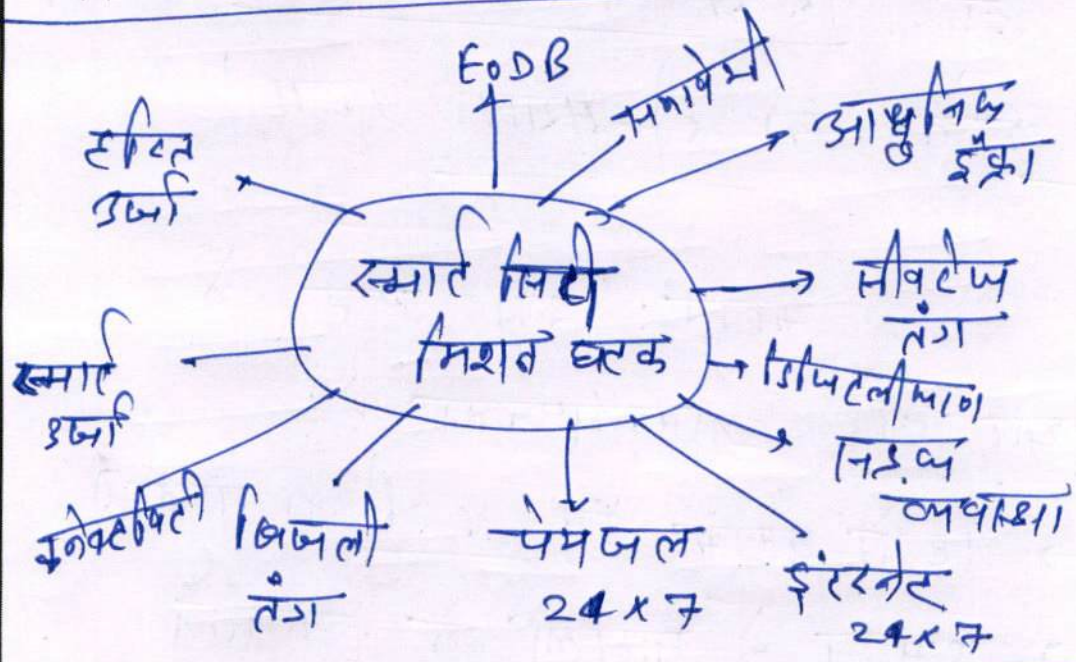

10 साल बाद स्मार्ट सिटी मिशन का आंकलन :-

सकारात्मक :- ① मदुरै 100% सफल शहर बना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

② शहरों की Ease रैंकिंग में सुधार → भारत की Rank 2014 (134) से 63rd (2019)

③ FDI बढ़ना

④ Tier-2 व Tier-3 शहरों का विकास :-
- → 40% जनसंख्या
- → 40% Start up
- → उद्योग → IT
- → etc

⑤ रोजगार सृजन व नियोजित पलायन → 100 शहरों में विकेंद्रीकृत रोजगार

⑥ स्वच्छ व निर्मल, हरे भरे शहर

कमियाँ :-

① 7980 के अनुमानित प्रोजेक्ट में से मात्र 6500 के आसपास ही क्रियान्वयन।

② नगरों के शहरों में शहरी बाढ़
उदा० - चेन्नई, दिल्ली

③ योजनाओं का अतिव्यापन व मंत्रालयी समन्वय का अभाव
Ex - हृदय, अमृत योजना

④ स्मार्ट शहर, स्मार्ट गांवो के बिना अधारणीय। - गांवो से गरीब व बेरोजगार लोग शहरों में झुग्गी बस्ती। Ex धारावी

⑤ प्रदूषण - दिल्ली वायु प्रदूषण
- 10 विश्व के प्रदूषित शहरों में 9 भारत में

⑥ ULB के पास शक्तियों का अभाव

सुझाव
- समावेशी मास्टर प्लान
- ULB को वास्तविक 3F का विकेंद्रण
- हरित स्मार्ट सिटी
- मॉडल-गांव + स्मार्ट शहर समन्वित प्रणाली
- समय पर पैसे का हस्तांतरण
- परफॉर्मेंस आधारित प्रोत्साहन

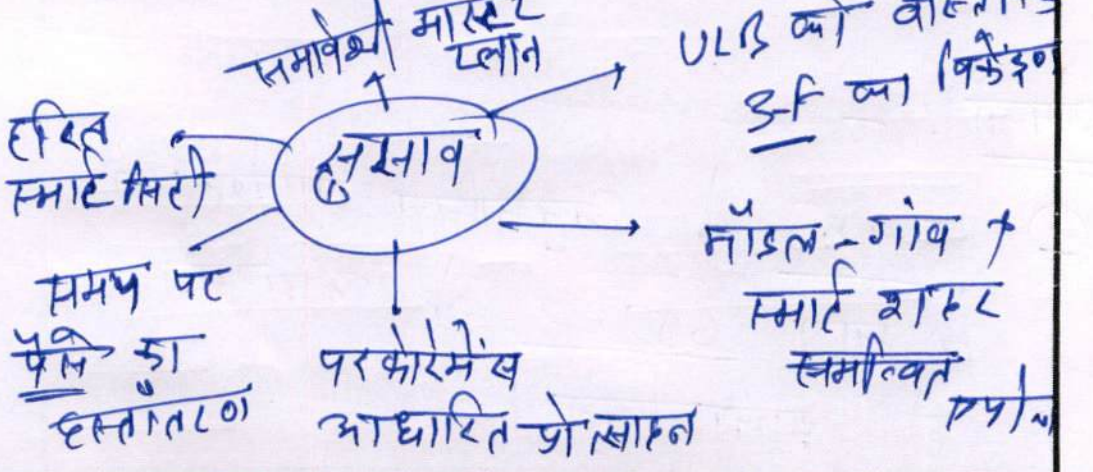

Q17. भारत में चरम निर्धनता में काफी कमी आई है, लेकिन स्वस्थ भोजन तक पहुंच अभी भी एक विलासिता का विषय बनी हुई है। स्वस्थ भोजन तक अपर्याप्त पहुंच के कारणों पर चर्चा कीजिए और उनका समाधान करने के उपाय सुझाइए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

While extreme poverty has declined considerably in India, access to healthy food still remains a luxury. Discuss the reasons for poor access to healthy food and suggest measures to overcome the same. (Answer in 250 words) 15

UNDP के डेटा के अनुसार भारत मे गरीबी दर 2014 (45%) से 2021 (16%) हो गई है

लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स मे भारत की रैंक 111 व 29.1 स्कोर के साथ भारत "Serious" श्रेणी मे शामिल है

जिसका मूल कारण भोजन भाग नहीं बल्कि स्वास्थ्य भोजन का अभाव है

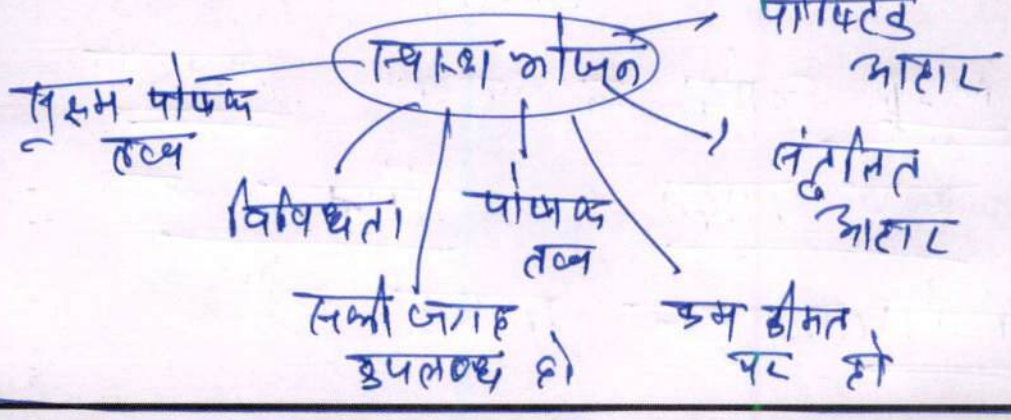

स्वास्थ्य भोजन तक पहुँच के सरकार के **प्रयास**:

- PDS योजना
- NFSA 2013
- ICDS योजना
- प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना
- पोषण मिशन
- वन नेशन वन राशन कार्ड
- PM उज्ज्वला योजना

अपर्याप्त पहुँच के कारण: —

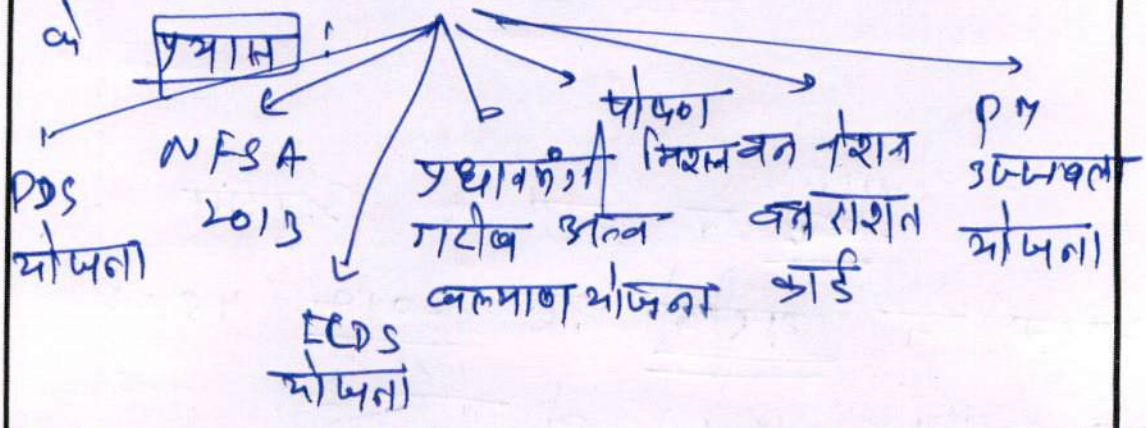

① खाद्यान्न आपूर्ति पर फोकस न कि स्वास्थ्य भोजन पर।

Ex- NFSA मात्र < गेहूं, चावल, बाजरा।

② स्वास्थ्य भोजन के मानकों का अभाव

③ वित्तीय बोझ — 2.5% GDP पहले ही सब्सिडी पर।

④ MSP आदि के कारण विकृत कृषि उत्पादन — पौष्टिक व विविधता युक्त उत्पादन नहीं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(5) छद्म भूख पर ध्यान नहीं व भूख की गहनता की उपेक्षा।

(6) रिसाव → NFSA का 40% रिसाव (शांताकुमार समिति)

समाधान उपाय :—

(1) A.E., UPS सहित आधार डेटा का विश्लेषण कर लाभार्थियों की सही पहचान

(2) खाद्यान्न → ~~फॉर्टिफाइड~~ भोजन की ओर जाना

(3) परिरक्षित भोजन की प्रौद्योगिकी व फोर्टिफिकेशन मे R&D व ~~कॉर्पोरेट~~ सहयोग पाना।

(4) स्वास्थ्य GDP को 1.34% से बढ़ाना

(5) परिवहन तंत्र आधुनिकीकरण

(6) विकेंद्रीकृत पोषण केंद्र व पूरक पोषण (7) मातृ पोषण आदि

फलतः पोषित भारत मे विदेशी देश की ~~जैविक~~ का आधार को

2368

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q18. भारत में स्वास्थ्य संबंधी परिणामों को बेहतर बनाने में सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा की भूमिका का परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Examine the role of publicly funded health insurance in improving health outcomes in India. (Answer in 250 words) 15

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2368

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q19. भारत की 'पड़ोस प्रथम (Neighbourhood First)' नीति पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने में किस हद तक सफल रही है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

To what extent has India's 'Neighbourhood First' policy been successful in enhancing its relations with the neighbouring countries? (Answer in 250 words) 15

पड़ोस प्रथम की नीति वस्तुत: गुजराल सिद्धांत का संशोधित रूप है जहाँ पड़ोसी देशों को प्राथमिकता दी जायेगी जिसमे उनसे वापसी पाने की कोई अपेक्षा न रखी जाये।

उदा० - नेपाल मे आपदा सहायता
- मालद्वीव मे जल संकट मे सहायता
- BAN को G-20 सम्मेलन मे आमंत्रण

इस नीति की आवश्यकता भारत की उस ~~बड़े~~ बिग ब्रदर की एकपक्षीय तानाशाही धारणा को तोड़ना व चीन को क्षेत्र मे प्रतिसंतुलित रूप निवल सुरक्षा प्रदाता व UNSC मे दावेदार बनना है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पड़ोस प्रथम नीति की सफलता :

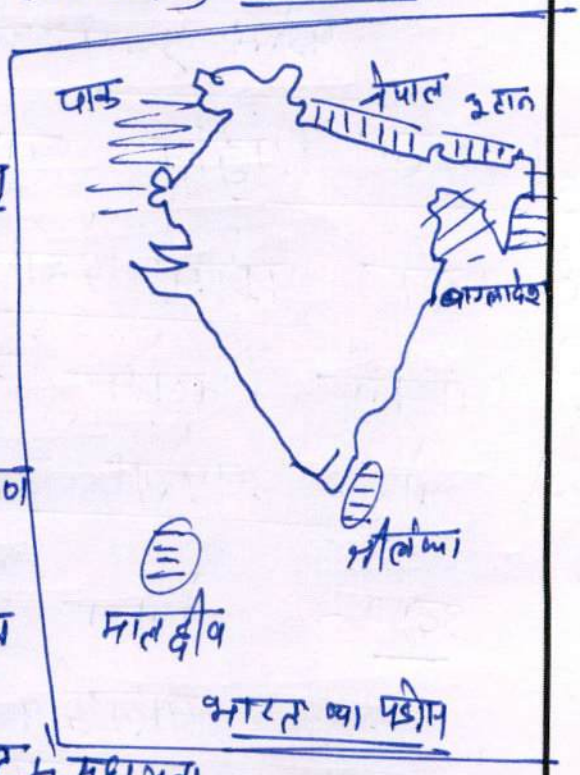

① बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक व्यापार व 100वां संविधान संशोधन द्वारा सीमा सुधार समझौता।

② नेपाल
- HADR
- आसान पहुंच
- पर्यटन
- जल विद्युत समझौते

③ श्रीलंका
- आर्थिक संकट में सहायता
- त्रिंकोमाली पत्तन का विकास
- घनिष्ठता

④ भूटान :
- 98% व्यापार भारत के साथ
- भारत के PM को भूटान का सर्वोच्च सम्मान

⑤ सार्क समझौता, बिम्सटेक, IORA, BBIN, इंद्रा विकास, ITEC कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस से जुड़ना, SACEP आदि।

2368
VISION IAS™
Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियाँ :-

① पाकिस्तान से तनावपूर्ण संबंध
② चीन से सीमा पर सैन्य टकराव
③ चीन का प्रभुत्व बढ़ना -
→ नेपाल, मालद्वीव का चीन के साथ निकटता झुकाव
→ OBOR में सभी देश शामिल
→ पड़ोस देशों में एंटी इंडिया राजनीति
Ex - मालद्वीव में Exit India कैंपेन
- नेपाल द्वारा सहायता से इंकार
④ भारत की वित्तीय मजबूरियों व प्रोजेक्ट धीमे होने
Ex → EMT [illegible] मार्ग
⑤ पड़ोस में अस्थिरता - BBIN लागू न होना
→ सार्क में नगण्य व्यापार
फलत: बिग ब्रदर की हेजेमोनी वाली छवि तो समाप्त हुई है लेकिन चीन के रूप में नया संकट उभरा है

सुझाव → ग्लोबल साउथ के नेता बनना
→ देशों को साथ सम्मान पूर्वक संबंध
→ चीन से बेहतर विकल्प देना
→ MAGA [illegible]

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q20. पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्षों के भारत पर पड़ने वाले उल्लेखनीय प्रभावों को रेखांकित करते हुए इसके क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Examine the effects of escalating conflicts in West Asia on regional and global stability, highlighting the significant repercussions for India. (Answer in 250 words) 15

पश्चिमी एशिया वर्तमान मे संघर्ष व भू-राजनीति का केंद्र बना हुआ है जो भारत की व्यापारिक सहित, रणनीतिक स्थायता को चुनौती प्रस्तुत करता है।

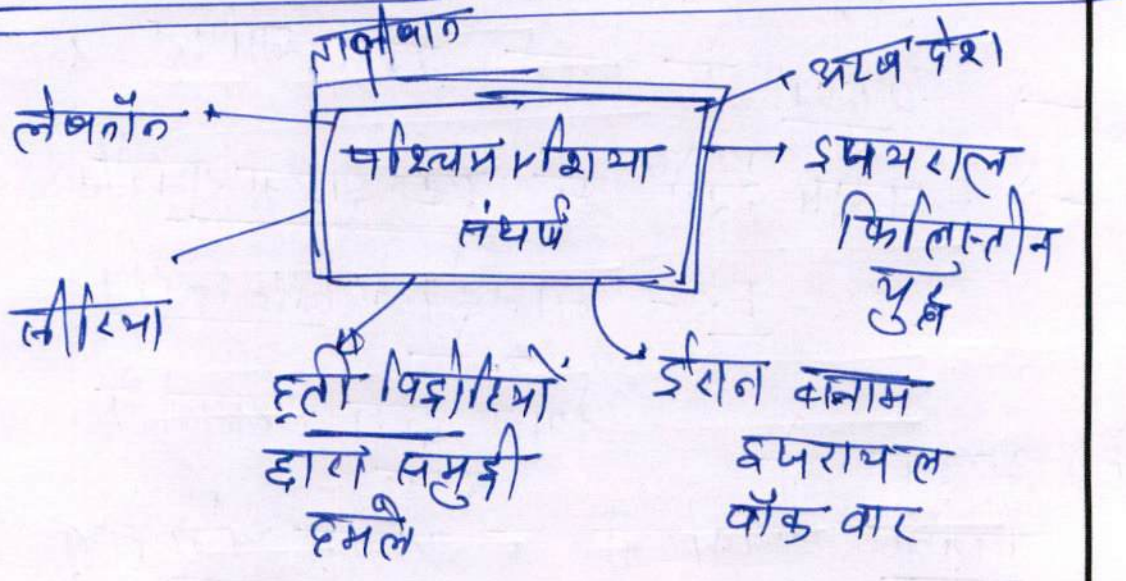

भारत पर प्रभाव। —

1. ऊर्जा सुरक्षा। → 85%. ऑयल का आयात
   → ऑयल मंहगा होना
2. आर्थिक — व्यापार पतन, डॉलर कम होना
   — आंतरिक मंहगाई
3. रणनीतिक → इजरायल बनाम ईरान, USA बनाम रूस मे स्थायता व

डि-हाइफनेशन बनाम रचना जटिल

④ सुरक्षा — हिंसा, आतंक प्रसार
सुरक्षा, पाकिस्तान व
चीन का प्रभाव बढ़ना।

⑤ प्रवासी भारतीयों के हितों व विप्रेषण
पर संकट

क्षेत्रीय व वैश्विक स्थिरता पर प्रभाव:

① राजनीतिक अस्थिरता बढ़ना —
② फिलिस्तीन को लेकर ध्रुवीकरण
③ हथियार होड़ बढ़ना
④ अब्राहम समझौते की भावना
विफल
⑤ विश्व के व्यापार पर नकारात्मक
प्रभाव।
⑥ बहुध्रुवीय युद्ध का खतरा
⑦

फलत: विश्व की आर्थिक,
पर्यावरणीय, सामाजिक स्थिरता नष्ट होगी

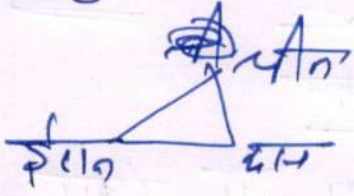

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

वैश्विक स्तर पर :- —

1. ईरान को लेकर देशों मे तनाव
उदा० → भारत ईरान से ऊर्जा आयातक लेकिन होती अंतक के खिलाफ
2. चीन व अमेरिका मे ध्रुवीकृत होने का खतरा
3. नये राजनीतिक समीकरण बनना → चीन शांति स्थापक बनना
→
4. वैश्विक प्रवास → मानव संकट
5. असुरक्षा का प्रसार
6. ~~कल्ल~~, UNSC की निष्क्रियता उजागर होना।
7. oil मूल्यों की अस्थिरता
8. ऊर्जा का वैश्विक संकट

अतः UN को कठोर कार्य करते हुए शांति स्थापना के लिए सभी P-5 को एक साथ जोड़ना होगा